भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1496
28 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना की समीक्षा

1496. **श्री के. ई. प्रकाशः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने अनुमोदित परियोजनाओं, निवेशों और लाभार्थियों के भौगोलिक वितरण के संदर्भ में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की भागीदारी की समीक्षा की है;

(ख) क्या सरकार को विशेष इस्पात और संबद्ध विनिर्माण क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना में तमिलनाडु सहित लाभार्थी विनिर्माण सुविधाओं के अधिक स्थानीयकरण के संबंध में उद्योग संगठनों इस्पात निर्माताओं और एमएसएमई से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार का उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के मौजूदा और भविष्य के चरणों के अंतर्गत तमिलनाडु के इरोड जिले सहित औद्योगिक समूहों, जहां इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन एमएसएमई कार्यरत हैं, में एमएसएमई-आधारित इस्पात और इंजीनियरिंग इकाइयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किन्हीं उपायों का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन ढांचे के माध्यम से निवेश के व्यापक क्षेत्रीय प्रसार, मूल्यवर्धित इस्पात विनिर्माण और डाउनस्ट्रीम औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई नीतिगत पहल विचाराधीन हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में भाग लेने के लिए, किसी कंपनी का भारत में पंजीकृत होना अनिवार्य है, निवेश और क्षमता सीमा का पालन करते हुए विशेष इस्पात उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, और प्रतिबद्ध निवेश के कम से कम 30 प्रतिशत के बराबर निवल संपत्ति (नेट वर्थ) होना आवश्यक है। एमएसएमई सहित कंपनियों की व्यापक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए, योजना के तीसरे चरण में पात्रता मानदंडों में ढ़ील दी गई थी।

यह योजना भारत के सभी राज्यों के लिए लागू है। 15 राज्यों से 100 कंपनियों की 167 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें तमिलनाडु की छह परियोजनाएं शामिल हैं।

*****